साप्ताहिक

जागत गांव हमार

पंचायत की विकास गाथा, सरकार तक

RNI-MPHIN/2015/72544

भोपाल, सोमवार 27 मार्च-02 अप्रैल , 2023, 2023, वर्ष-8, अंक-50

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, मुरैना, रीवा, शिवपुरी से एक साथ प्रकाशित

पृष्ठ :-8, मूल्य :- 2 रुपए

चौपाल से भोपाल तक

-2050 तक चावल, गेंहू और मक्के की पैदावार में भारी कमी आएगी

» चावल में 20, गेंहू में 19.3 और बाजरे में 18 फीसदी गिरावट होगी

» भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्टडी में चौंकाने वाला खुलासा

सावधान! अगले 27 साल में नहीं मिलेगा चावल-गेहूं और मक्का!

भोपाल। जागत गांव हमार

जलवायु संकट की वजह से भविष्य में अनाज की पैदावार पर असर पड़ेगा। सिर्फ मौसम संबंधी आपदाएं नहीं आएंगी, बल्कि उसका सीधा असर कृषि और फलों की खेती पर पड़ेगा। क्योंकि जिस तेजी से एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स यानी मौसम का तेजी से बदलना और उससे जुड़ी आपदाएं आ रही हैं। देश में लोग दाने-दाने को मोहताज हो सकते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कृषि क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन की वजह से होने वाले असर की स्टडी की। स्टडी में जो नतीजे सामने आए, वो डराने वाले हैं। शोध में दावा किया गया है कि 2050 तक बारिश से होने वाली धान की फसल की पैदावार में 20 फीसदी की गिरावट आएगी, जो 2080 तक 47 फीसदी घट जाएगी। वहीं जिस धान की फसल की सिंचाई की जाती है, वो 2050 तक 3.5 फीसदी गिर जाएगी। जबकि 2080 तक 5 फीसदी गिर जाएगी। यही नहीं, जलवायु परिवर्तन की वजह से गेंहू की फसल में 2050 तक 19.3 फीसदी की गिरावट आएगी। जबकि 2080 तक यही बढ़कर 40 फीसदी हो जाएगा। ऐसा ही कुछ मक्का के साथ भी है। 2050 तक मक्का की फसल में 18 फीसदी और 2080 तक 23 फीसदी की गिरावट होने की आशंका है। भारत के मध्य इलाके में यानी गुजरात, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में 1 जनवरी से 31 अक्टूबर 2022 के बीच 198 दिनों तक खतरनाक मौसम था। मध्यप्रदेश सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य रहा।1.36 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन पर लगी फसलें खराब हो गईं।

18.1 लाख हेक्टेयर फसल बर्बाद

एक रिपोर्ट अभी सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट ने रिलीज की है। जिसमें बताया है कि भारत में पिछले साल 1 जनवरी से लेकर 31 अक्टूबर तक 304 दिनों में 271 दिन मौसम खराब ही रहा है। वो भी आपदाओं के तौर पर। कभी सूखा तो कभी बाढ़। कभी ओले तो कभी आंधी-तूफान। 18.1 लाख हेक्टेयर जमीन पर लगी फसल बर्बाद हो गई। पूर्वी और उत्तर-पूर्वी राज्यों में 191 दिनों तक एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स थे। यहां बिहार, झारखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय हैं। खराब मौसम की वजह से 2.85 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन पर लगी फसलें खराब हुई। सबसे बुरी हालत असम की रही।

इन राज्यों में खेती प्रभावित

उत्तर और उत्तर-पश्चिम राज्यों यानी जम्मू-कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान ने सबसे ज्यादा 216 दिनों तक खराब मौसम का सामना किया है। इनमें सबसे ज्यादा बुरी हालत उत्तर प्रदेश की रही। 3.11 लाख हेक्टेयर जमीन पर लगी फसलें खराब हो गईं। अगर दक्षिण भारत की बात करें तो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में खराब मौसम के कुल 145 दिन थे। सबसे बुरी हालत कर्नाटक की रही। 10.73 लाख हेक्टेयर जमीन पर लगी फसलें खराब हुईं।

सरकार अपने अलग-अलग मंत्रालयों और विभागों के जरिए जलवायु परिवर्तन और उससे पड़ने वाले असर पर नजर रख रही है। नए डेटा और वैज्ञानिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन ये भी तय है कि जलवायु परिवर्तन का असर भविष्य में होने वाली पैदावार पर पड़ेगा।
अश्विनी कुमार चौबे, केंद्रीय राज्यमंत्री

तहसील में 150 आलू चिप्स कारखाने हो रहे संचालित

महू में बनेगा प्रदेश का पहला आलू चिप्स क्लस्टर

इंदौर। जागत गांव हमार

जिले की महू तहसील में प्रदेश का पहला आलू चिप्स क्लस्टर बनाया जाएगा। मानपुर के पास कुवाली में 20 एकड़ जमीन पर बनने वाले क्लस्टर में प्रोसेसिंग यूनिट, स्टोरेज और एक्जीविशन सेंटर सहित मिलेगी तमाम आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। साथ चिप्स कारखानों से निकलने वाले दूषित पानी से प्रदूषित हो रही नदियों को बचाया जा सकेगा। चिप्स क्लस्टर में इंफ्लूएंट ट्रीटमेंट प्लांट (ईटीपी) प्लांट लगाया जाएगा। इससे पहले दूषित पानी को फिल्टर करने के बाद नदियों में छोड़ा जाएगा। भारत सरकार के माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम (एमएसई-सीडीपी) सोजना के तहत बनने वाले इस प्रोजेक्ट की कीमत लगभग 15 करोड़ है।

केंद्र 60, राज्य 40 फीसदी लागत करेगा वहन

एमएसई-सीडीपी के तहत 15 करोड़ का प्रोजेक्ट तैयार किया जा सकता है। इसके लिए केंद्र 60 और राज्य 40 फीसदी लागत वहन करती है। जिला उद्योग केंद्र के जीएम एसएस मंडलोई ने बताया कि यह चिप्स क्लेस्टर प्रदेश का पहला है। इसमें पहले बिजली, पानी, सड़क आदि भूलभूत सुविधाएं तैयार की जाएगी। हालांकि प्रोजेक्ट की डीपीआर बनने में ही 2 से 3 महीने का समय लग जाएगा।

गर्मियों में संचालित होते हैं 150 कारखाने

तहसील के कोदरिया और आस-पास के क्षेत्रों में गर्मियों के दौरान 150 से अधिक कारखाने संचालित किए जाते हैं। इनमें आलू चिप्स तैयार की जाती है। यह चिप्स देशभर के साथ विदेश भी भेजी जाती है। इन चिप्स कारखानों के चलते इन कारखानों से नदियां प्रदूषित हो रही हैं। अब प्रशासन इन कारखानों को एक जगह पर लाने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए मानपुर के पास कुवाली में राजस्व विभाग की 15 से 20 एकड़ जमीन चिह्नित की गई है।

खेती में उपयोग होगा पानी

आलू चिप्स बनाने के लिए निकलने वाले स्टार्च को ईटीपी प्लांट की मदद से अलग कर दिया जाएगा। जिसके बाद इस पानी को सिंचाई में भी उपयोग किया जा सकता है। यहां कारखानों में तैयार चिप्स गुजरात, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली सहित अन्य राज्यों में जाती है। फिर के बाद वहां से नेपाल, खाड़ी देश, पाकिस्तान सहित अन्य देश में जाती है।

20 हजार को मिलेगा रोजगार

वर्तमान में 150 से अधिक कारखाने संचालित होते है, जहां पर 10 हजार से अधिक लोगों को रोजगार मिलता है। क्लस्टर बनने के लिए यह संख्या बढ़कर 20 हजार हो जाएगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को आएंगे भोपाल

भोपाल। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भोपाल आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस अवसर पर यहां पहली बार आयोजित कार्यक्रम को संबोधित और पंचायत के प्रतिनिधियों से बात करेंगे। इस कार्यक्रम में

विभिन्न क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रहीं देशभर से चुनी गई पंचायतों को पुरस्कृत किया जाएगा। राज्य सरकार ने कार्यक्रम की तैयारी शुरू कर दी है। यह कार्यक्रम राजधानी के जंबूरी मैदान पर आयोजित किया जा सकता है और इसमें प्रदेशभर से पंचायत प्रतिनिधि शामिल होंगे। कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की जा रही है, जिसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अंतिम रूप देने का निर्णय लेंगे। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री एक अप्रैल को भी भोपाल आ रहे हैं। यहां कुशाभाऊ ठाकरे हाल में रक्षा मंत्रालय की एक बैठक होगी, जिसमें वे शामिल होंगे।

-मध्यप्रदेश में 132 करोड़ होंगे खर्च,पहले शहरों पर फोकस

-क्षमता के साथ आश्रित गौवंश को लेकर रिपोर्ट तैयार होगी

गौशालाएं होंगी स्मार्ट

भोपाल। चुनावी साल में सरकार ऐसे मुद्दों पर फोकस कर रही है जो धर्म से लेकर सियासत का केंद्र रहे हैं। अब सरकार ने गौशालाओं को अत्याधुनिक गौशालाओं में तब्दील करने का निर्णय लिया है। बीते एक साल में प्रदेश से गोशालाओं के बदहाली की कई तस्वीरें सामने आई थीं। राजधानी भोपाल के ग्रामीण अंचल में सैकड़ों की संख्या में गौवंश के कंकाल मिले। विपक्ष ने गौवंश संरक्षण को मुद्दा बनाकर सरकार की कार्यप्रणाली पर कई सवाल भी खड़े किए थे। अधिकारियों ने बताया कि स्मार्ट गोशालाओं के नए प्रोजेक्ट में पशुपालन विभाग, नगरीय प्रशासन और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग संयुक्त रूप से काम करेंगे। प्रोजेक्ट पर चरणबद्ध तरीके से काम किया जाएगा। पहले चरण में सरकार ने शहरी क्षेत्र की गौशालाओं को हाईटेक करने का फैसला लिया है। फिर उन गौशालाओं पर फोकस होगा जो ग्रामीण क्षेत्रों में हैं और गायों की संख्या अधिक है। प्रोजेक्ट के पहले चरण में निर्माण की राशि छोड़कर 132 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है।

सियासत पर फोकस

प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सरकार का फोकस दिखाई दे रहा है। सरकार ने हाल ही में धार्मिक शहरों के अलग से मास्टर प्लान बनाने का निर्णय लिया है। तो एमपी की जीवनदायिनी नर्मदा नदी के संरक्षण को लेकर भी अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बनकर तैयार है। अब गोशालाओं की बदहाली दूर करने के लिए स्मार्ट गोशाला प्रोजेक्ट।

यह हमारा अद्भुत प्रयास- मंत्री

नगरीय विकास एवं आवास विभाग राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया ने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर लगातार नवाचार किए जा रहे हैं। स्मार्ट गौशालाओं का प्रयास भी अद्भुत है। गौशालाओं की अब तस्वीर बदलने के लिए काम होगा। पहले शहरी फिर ग्रामीण अंचल की गौशालाओं की तस्वीर बदली जाएगी। कांग्रेस के समय करोड़ों रुपये की धांधली की गई। कांग्रेस ने गोवंश के चारा-भूसा तक को नहीं छोड़ा।

स्मार्ट गौशाला बनाने 10 बिंदुओं पर होगा अमल

1 - पहले होगी रिपोर्ट तैयार

गौशालाओं की क्षमता के साथ आश्रित गौवंश को लेकर रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इसमें रिपोर्ट में स्थान, शेड या कच्चा-पक्का निर्माण का खाका होगा। यदि अतिरिक्त स्थान है तो उसका भी खाका तैयार किया जाएगा।

2- फिर शुरू होगा निर्माण

ऐसी गौशालाएं जो शेड या कच्चे निर्माण में संचालित हो रही हैं उन्हें पक्के स्ट्रक्चर में तब्दील किया जाएगा। यदि स्थान की कमी है तो अन्य स्थान पर निर्माण किया जाएगा। निर्माण भी भविष्य में गौवंश की संख्या के आधार पर होगा।

3- गौशालाओं का होगा कोड

स्मार्ट गौशाला प्रोजेक्ट में यह कदम महत्वपूर्ण है। गौशाला के साथ इनमें आश्रित एक-एक गौवंश का कोड होगा। इस कोड के जरिए ही डाटा और तमाम जानकारी दर्ज की जाएंगी।

4- डिवाइस से होगी पहचान

गौवंश के कान में सेंसर डिवाइस भी लगाया जाएगा। इससे 24 घंटे निगरानी और मौजूदा स्थिति पता चल सकेगी। यह भी स्पष्ट होगा कि गाय गोशालाओं में या बाहर। समय का भी पूरा खाका अपने आप अपडेट होगा।

5- निगरानी के लिए पोर्टल

प्रोजेक्ट के तहत पशुपालन विभाग एक पोर्टल भी बनाएगा। इसमें गौशाला के संधारण, दानदाताओं और सरकार से मिली राशि का हिसाब होगा। किस मद में कितना खर्च किया गया, इसकी जानकारी पोर्टल में मिलेगी। खास बात यह है कि यह जानकारी कोर्ट के जरिए सभी देख सकेंगे।

ऐसा भी होगा पहली बार

गौवंश का हेल्थ चेकअप भी किया जाएगा। तारीख, समय, डॉक्टर का नाम, बीमारी, दवाओं की जानकारी पोर्टल पर दर्ज होगी। इसके अलावा चारा-भूसा समेत अन्य खाने-पीने के लिए दी जाने वाली सामग्री की भी जानकारी ऑनलाइन दर्ज कराई जाएगी।

गोशालाओं कंट्रोल रूम

स्मार्ट गौशालाओं को लेकर कंट्रोल रूम भी बनाया जाएगा। इस कंट्रोल रूम का उद्देश्य मॉनिटरिंग के साथ डाटा संग्रहण और रिपोर्ट होगा। स्मार्ट गौशालाओं के नोडल अधिकारी के पास कंट्रोल रूम से प्रतिदिन रिपोर्ट भी भेजी जाएगी। ताकि रखरखाव के साथ बेहतर प्रबंधन किया जा सके।

शिकायत दर्ज करा सकेंगे

गौशालाओं के बेहतर प्रबंधन के लिए यह नवाचार अहम है। पोर्टल में ऑनलाइन कोड के जरिए किसी भी प्रकार की शिकायत या सुझाव को दर्ज कराया जा सकेगा। नोडल अधिकारी इन पर अमल करेगा। साथ ही पोर्टल पर शिकायत की स्थिति और निराकरण की जानकारी भी दर्ज की जाएगी।

गौशाला का स्मार्ट ऑडिट

स्मार्ट गौशालाओं का स्मार्ट ऑडिट भी किया जाएगा। व्यवस्था के सुधार के लिए इसका कोई समय निर्धारित नहीं किया गया है। मोबाइल पर पोर्टल के जरिए रियल टाइम फोटो और वीडियो के निर्देश भी होंगे। ताकि वास्तविक स्थिति की जानकारी पता लगाई जा सके।

सीसीटीवी की सुविधा

गौशालाओं के उत्पाद में शामिल दूध, कंडे आदि की जानकारी भी ऑनलाइन दर्ज होगी। बड़ी गौशालाओं में केयर रूप की सुविधा भी होगी। सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे। फायर सिस्टम, अलार्म सिस्टम, सोलर प्लांट, रैन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, कवर्ड ब्लॉक, ऑटो ट्राली सिस्टम, ऑटो वॉसिंग सिस्टम, ओपन स्पेस समेत अन्य सुविधाएं भी होंगी।

मध्यप्रदेश में 1687 गौशालाएं पर लाखों का भार

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक मध्यप्रदेश में कुल 1687 गौशालाएं (सरकारी और प्राइवेट) हैं। इनमें करीब 2 लाख 75 हजार गौवंश आश्रित हैं। गौशालाओं के संचालन के लिए सरकार 131 लाख 84 करोड़ रुपए का अनुदान देती है। दानदाताओं समेत कई संस्थाएं गौशालाओं को राशि दान करती हैं। प्रोजेक्ट में पहले शहर सीमा क्षेत्र में आने वाली गौशालाओं की बदहाली दूर करने पर काम किया जाएगा।

स्मार्ट गोशाला का फायदा

एमपी में सड़कों पर गौवंश की बड़ी समस्या रही है। रात के वक्त न सिर्फ लोग हादसों का शिकार होते हैं बल्कि गायों की मौत के मामले कम नहीं है। अकसर यह देखा गया है कि गोशालाओं के कागजी आंकड़ों में ही गौशालाओं में गायों को आश्रय मिलता है। जिम्मेदारों की लापरवाही को लेकर कई बार सख्त कार्रवाई के निर्देश भी जारी हो चुके हैं। लेकिन इस मनमानी रोकना सरकार के लिए बड़ी चुनौती रही है।

-पशुपालन, नगरीय और पंचायत विभाग संयुक्त काम करेंगे

-वैज्ञानिकों ने देशी गाय पर शोध कर बढ़ाई उपयोगिता

गायों पर किए गए शोध से लोगों की सोच बदली

अभी तक जो लोग देशी गाय की उपयोगिता को सिर्फ उसके दूध से भांपते थे, वो आज उसके गोबर से बनते उत्पाद और गौमूत्र का दवाइयों में बढ़ता उपयोग देखकर अपनी सोच का दायरा बढ़ा रहे हैं। इस बीच जबलपुर के नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय ने पशु विज्ञानिकों ने देशी गाय पर किए शोध के परिणाम से सब कुछ बदल दिया है। जो देशी गाय दूध न देने की वजह से कल तक सड़कों पर निराश्रित घूमा करती थीं, वो आज विवि के फार्म पर शोध का अहम हिस्स बन गई है। विवि के पशुविज्ञानियों ने उसकी कोख में हाइब्रिड नस्ल की गाय के बच्चों को पैदा कर दिया है। खास बात यह है कि इन बछड़ों ने, निराश्रित देशी गाय की कोख में रहकर उनके वो सारे अच्छे गुण अपना लिए हैं, जिसके लिए वो पहचानी जाती थीं। पहली बार में सफलता मिलने के बाद अब दूसरी बार फिर निराश्रित गायों पर यह प्रयोग किया गया है।

विश्वविद्यालय के बायोटेक्नोलाजी के विभागाध्यक्ष डॉ.एपी सिंह बताते हैं कि जबलपुर डेरी फार्म में अपने कुछ ऐसी देशी गाय पर शोध करने का निर्णय लिया, जिन्हें लोग, दूध न देने की वजह से सड़कों पर छोड़ दिया करते थे। इनके लिए हमनें अपने पशु वैज्ञानिकों के साथ उत्तराखंड और मध्यप्रदेश पशुपालन विभाग के पशुविज्ञानिकों की मदद ली। हमने 14 देशी गायों को चुना, जो कमजोर थीं। इन्हें अपने फार्म पर रखकर इनके स्वास्थ्य का परीक्षण किया और फिर इनकी कोख में सबसे ज्यादा दूध देने वाली साहीवाल गाय के भ्रूण को रखा। हमें पहली बार में ही सफलता मिल गई। 14 में से 8 गाय ने गर्भधारण कर 8 साहीवाल के बछड़ों को जन्म दिया। परिणाम अच्छे आने के बाद 17 गायों में भी भ्रूण प्रत्यारोपण किया गया है।

फायदे बताने उठाया कदम

जबलपुर के पशुपालकों के साथ बैठक कर वेटरनरी विश्वविद्यालय और विभाग के डाक्टर, लगातार उन्हें देशी गाय की उपयोगिता बताकर उनसे आय कमाने का प्रशिक्षण दे रहे हैं। विवि के अधारताल फार्म में देशी गाय के गोबर से गमले बनाने से लेकर मॉस्किटो क्वाइल, जलाई लकड़ी, हवन सामग्री जैसे आइटम बनाकर रखे हैं। वहीं इन उत्पादों को बनाने का प्रशिक्षण भी दे रहे हैं, ताकि देशी गाय के दूध न देने पर वे उन्हें सड़कों पर निराश्रित न छोड़े। देशी गाय के गौमूत्र को उपयोग विवि द्वारा फिनाइल बनाने से लेकर कई मेडिसिन में किया जा रहा है। इसके साथ ही विवि के मेडिसिन विभाग गौमूत्र की उपयोगिता में अनुसंधान भी कर रहा है।

देशी गाय इसलिए खास

- इन गायों में रोग प्रतिरोधक क्षमता, विदेश नस्ल और हाइब्रिड नस्लों की तुलना में ज्यादा होती है।
- इनके लिए सामान्य आहार, घास-भूसा ही पर्याप्त होता है।
- इसका सिर्फ दूध ही पौष्टिक नहीं होता बल्कि गोबर, गौमूत्र भी उपयोगी है।
- इसके धार्मिक और अध्यात्मिक पहलुओं से यह महत्वपूर्ण हैं।

अब गाय भी देगी सरोगेसी तकनीक के जरिए बछड़े को जन्म

लखनऊ। बरेली स्थित भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ने सरोगेसी तकनीक का सफल परीक्षण किया है। वैज्ञानिकों ने बताया कि सरोगेसी तकनीक के जरिए अब तक 26 बछड़ों का प्रजनन हो चुका है। सिर्फ इंसान ही नहीं, बल्कि अब गायें भी सरोगेसी तकनीक से बछड़े को जन्म देंगी। बरेली स्थित भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ने सरोगेसी तकनीक का सफल परीक्षण किया है। कहा जा रहा है कि अब इंसान की तरह गायों से भी सरोगेसी तकनीक के जरिए बेहतर नस्ल के बछड़े प्राप्त किए जा सकते हैं। संस्थान के वैज्ञानिकों ने बताया कि सरोगेसी तकनीक के जरिए अब तक 26 बछड़ों का प्रजनन हो चुका है। दरअसल, सरोगेसी तकनीक के जरिए वैज्ञानिक अच्छी नस्ल के सांड के वीर्य को एकत्र कर लेते हैं। इसके बाद चुनी हुई नस्ल के अंडे लेकर भ्रूण तैयार करते हैं। फिर, भ्रूण को गाय में प्रत्यारोपित किया जाता है। इससे गाय बेहतर नस्ल के बछड़े को जन्म देती है, जो कि अधिक मात्रा में दूत देती है।

-देश में पहली बार हुई रिसर्च

वीयू के वैज्ञानिकों के शोध से छह गाय फिर से गर्भवती

गाय को बांझपन से निजात दिलाएगी इंसानों वाली दवा

जबलपुर। गौवंश में प्रसव के बाद बांझपन से निजात दिलाने के लिए देश पहली बार वेटरनरी यूनिवर्सिटी जबलपुर के वैज्ञानिकों ने इंसानों में गर्भपात के लिए उपयोग की जाने वाली दवा से इसका रास्ता खोज लिया है। अनुसंधान कर रहे वैज्ञानिकों के सफल परिणाम के तौर पर 6 गौ वंश ऐसे रहे जो कि) विवि लगातार पशुओं के संवर्धन और संरक्षण की दिशा में काम कर रहा है। कुलपति डॉ. एसपी तिवारी ने कहा कि प्रसव के बाद बांझपन से पीड़ित पशु पालकों के लिए यह एक बड़ी समस्या थी, जिससे राहत मिलेगी। अब वे गाभिन हो गए। इस दिशा में यह शोध मील का पत्थर साबित होगा।

34.4 प्रतिशत गो-वंश होते हैं पीड़ित

नानाजी देशमुख वेटरनरी साइंस यूनिवर्सिटी के वरिष्ठ वैज्ञानिक व एसी. प्रोफेसर डॉ. नितिन बजाज ने बताया आंकड़ों के मुताबिक करीब 100 में से 34.4 प्रतिशत गोवंश इस बीमारी से पीड़ित होते हैं। इसे देखते हुए उन्होंने अपनी टीम के साथ अनुसंधान कार्य शुरू किया। इसमें इंसानों व श्वानों में गर्भपात के लिए उपयोग की जाने वाली दवा मायकी प्रिस्टोन का उपयोग किया, जो सफल रहा। इससे बांझपन से पीड़ित 6 गाय गर्भवती हो गई हैं।

मोटे अनाजों का प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन

डा. शालिनी चक्रवर्ती

वरिष्ठ वैज्ञानिक (खादय विज्ञान), कृषि विज्ञान केन्द्र, राजगढ़।

राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर म.प्र.

पोषण की दृष्टि से कहीं ज्शादा बेहतर मोटे अनाज का भोजन में उपयोग परंपरागत उपभोक्ताओं तक ही सीमित हैं। मोटे अनाजों को खाने योग्य बनाने मूल्य सवर्धित खाद्य सामग्री बनाने की प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी का अभाव होने के कारण यह लोगों में ज्यादा लोकप्रिय नहीं हो पाए। मोटे अनाज, मूल्य सवर्धन तथा विविध उपयोग के लिए कई अवसर प्रदान करते हैं। उचित प्रसंस्करण के साथ मोटे अनाजों को विभिन्न तकनीकियों जैसे अंकुरण, दलाई, माल्टिंग, फुलाना आदि द्वारा खाने योग्य बनाया जा सकता है।

दलाई: हाल के वर्षों में मोटे अनाजों की दलाई की कई नई तकनीकों को विकसित किया गया है, जिससे लगने वाले समय तथा ऊर्जा दोनों को बचाया जा सकता हैं। आजकल घरेलू तथा बड़े पैमाने पर मोटा अनाज चक्की उपलब्ध हैं परंपरागत तकनीक से दराई करने पर भूसी तथा चोकर अलग अलग हो जाती है। दरे हुए मोटे अनाज से विभिन्न प्रसंस्कृत उत्पाद तैयार किये जा सकते हैं जैसे फ्लैक्स, जल्दी पकने वाले अनाज, पूरक आहार माल्ट आधारित उत्पाद, बच्चो के लिए पोषक आहार इत्यादि।

माल्टिंग: माल्टिंग की प्रक्रिया में अनाज को गीला करना तथा उनको अंकुरित करना सम्मिलित है। आमतौर पर अनाज को 16-24 घंटे के लिए भिगो देते हैं जिससे दाने पर्याप्त रूप से नमी अवषोषित कर लेते है और अंकुरित हो जाते हैं। माल्टेड ज्वार का प्रयोग कई देशों द्वारा किया जा रहा है। अंकुरित ज्वार से कई प्रकार के मादक पेय तैयार किये जाते हैं। माल्टिंग प्रक्रिया में अमीनों अम्ल की सरचंना में परिवर्तन आता है, स्टार्च शर्करा में परिवर्तित होता हैं। शरीर में वसा , विटामिन तथा खनिज की उपलब्धता में सुधार आता हैं। अंकुरित अनाज के आटे की, सामान्य आटे की तुलना में गर्म पानी के साथ मिलाने पर गाढ़ा करने की क्षमता काफी कम हो जाती हैं। अत: सामान्य आटे की तुलना में अंकुरित अनाज का आटा तीन गुना उपभोग किया जा सकता है। इससे उच्च कैलोरी घनत्व वालाा उत्पाद तैयार किया जा सकता हैं। छोटे बच्चे के आहार में यदि इन उत्पादों को स्थान दिया जाये तो उनको आहार की मात्रा बिना बढ़ाये ही उच्च कैलोरी आहार दिया जा सकता हैं। जो कि कुपोषण की समस्या को बहुत हद तक कम कर सकतें हैं। भारत में रागी माल्ट, बाजरा व ज्वार के माल्ट से ज्यादा स्वादिष्ट, पौष्टिक एवं लोकप्रिय हैं।

फुलाना: सामान्यत: रागी के दानों को फुलाकर प्रयुक्त किया जाता हैं, क्योंकि अन्य मोटे अनाजों की अपेक्षा रागी को फुलाने पर अधिक कुरकुरा व अच्छी सुगंध वाला उत्पाद तैयार होता हैं। फूले हुऐ मोटे अनाज रेशे तथा कार्बोज के अच्छे स्त्रोत हैं। मध्यम मोटी फली तथा कड़क एण्डोस्पर्म वाले मोटे अनाजों को फुलाना बेहतर साबित हुआ हैं। फुलाने की प्रक्रिया के दौरान लाइपोलिटिक एन्जाइम विकृत हो जाते हैं तथा इससें तैयार उत्पादो की उम्र बढ़ जाती हैं। मोटे अनाजों को फुलाने के पश्चात्

नाश्ते के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता हैं। फूले हुऐ मोटे अनाजों को नमक और मसाले के साथ या लडडू, सत्तू तथा चिक्की के रूप में मिठाई की तरह सेवन किया जा सकता हैं। फूले हुऐ मोटे अनाजों के आटे को भुनी हुई दालों जैसे काले चने एवं गुड़ या चीनी के साथ मिश्रित कर बच्चों एवं धात्री महिलाओं के लिए एक पूरक आहार तैयार किया जा सकता हैं जिससे प्रोटीन, लौह तत्व के साथ सभी अन्य आवश्यक पोषक तत्वों की प्राप्ति हो सकेगी। पोषण से भरपूर होने के साथ साथ मोटे अनाज से बनाये गए भोज्य पदार्थ बहुत ही कम मूल्य के भी होते हैं जो कि हर वर्ग के लोगों द्वारा आसानी से ग्रहण किये जा सकते हैं।

मोटे अनाज सूक्ष्म पोषक तत्वों एवं फाइटोकेमिकल्स के भरपूर स्त्रोत हैं अत: इस तरह के उत्पाद चावल तथा गेहूँ से बने इसी तरह के उत्पादों से अधिक गुणवत्ता रखतें हैं।

बेकिंग: किसी भी प्रकार का आटा बेकिंग के लिए उपयुक्त होता हैं। ग्रामीण इलाकों में तो पहले से ही मोटे आनाज की रोटी प्रचलित हैं। शहरी क्षेत्रो में पतली रोटी खायी जाती हैं अत: सामान्य आटे के साथ मोटे अनाज के आटे को मिलाकर रोटी या चपाती के रूप में प्रयुक्त किया जाता हैं। इसी मिश्रित आटे से बिस्किट, केक , कुकी आदि भी बेक की जा सकती हैं।

एक्सट्रूजन कुकिंग: यह बहुत ही लोकप्रिय प्रसंस्करण विधि है, जिसका उपयोग चावल तथा मक्का के लिए किया जाता है। इस विधि से मोटे अनाजों के तुरन्त खाने योग्य भोज्य पदार्थ तैयार किये जा रहे हैं। इस विधि में , अनाजों को बहुत उच्च तापमान पर कम समय के लिए पकाया जाता हैं। इस प्रक्रिया में स्टार्च जिलेटिनाइज्ड हो जाता है तथा प्रोटीन असंतृप्त हो जाती है जिससे उत्पाद की पाचकता बढ़ जाती हैं। इस प्रक्रिया में पोषण विरोधी कारक भी निष्क्रिय हो जाते हैं तथा सूक्ष्मजीवी काफी हद तक नष्ट हो जाते हैं और उत्पाद का जीवन भी बढ़ जाता हैं। इस प्रक्रिया में उत्पाद को किसी भी पोषक तत्व से पूरित कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में छना हुआ आटा ही उपयोग में लाना बेहतर हैं नही तो चोकर या छिलके के कारण उत्पाद सही नही बनेगा।

अत: हम यह कह सकते हैं कि मोटे अनाजों को अपने दैनिक आहार में बड़ी सरलतापूर्वक सम्मिलित किया जा सकता हैं। मोटे अनाजों के पोषण गुणों से हम भलीभांति परिचित हो चुके हैं। भोजन मूल्य के साथ साथ इन सभी फसलों का चारा मूल्य भी हैं। जानवरों द्वारा भी यह फसलें बहुत पसंद की जाती हैं। यह फसलें कम उर्वरक मिटट्री, अम्लीय मिटट्री तथा क्षारीय मिटट्री में भी उगायी जा सकती हैं। पानी की आवश्यकता भी बहुत कम होती हैं। कृत्रिम उर्वरक की आवश्यकता भी नही होती हैं। कीट मुक्त फसले हैं अत: कीटनाशकों के उपयोग की भी आवश्यकता नही होती हैं। इस प्रकार से मोटे अनाजों को उगाकर तथा उनका उपयोग कर हम पर्यावरण सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा तथा आर्थिक सुरक्षा में अपना महत्वपूर्ण योगदान कर सकते हैं। किसानों के लिए जलवायु अनुरूप खेती के विकास के लिए यह एक उपयुक्त विकल्प हैं।

पशुओं में पेट के कीड़ों की समस्या के लक्षण एवं उनका निराकरण

» डॉ. सोनू कुमार यादव
» डॉ. अंजनी कुमार मिश्रा
» डॉ. राहुल चौरसिया
» डॉ. उपेंद्र सिंह नरवरिया
» डॉ. भावना अहिरवाल
» डॉ. दानवीर सिंह यादव
» डॉ. अशोक पाटिल
» डॉ. नरेश कुरेचिया

पीएचडी शोध छात्र, प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, पीएचडी शोध छात्र सहायक प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक

पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय रीवा, मप्र.

पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय मह्, मप्र.

पशुओं में पेट के कीड़े पशुओं में होने वाली सबसे आम लेकिन गंभीर बीमारीयों में से एक है। परजीवी संक्रमण भारत जैसे ऊष्ण कटिबन्धीय जलवायु वाले देशों में एक बड़ी समस्या है। आमतोर पर इस तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता, परंतु अगर पशुओं के पेट में कीड़े हो गए तो धीरे-धीरे उनका स्वस्थ बिगड़ता ही जाता है और बाद में जाकार बड़े इलाज की जरूरत पड़ती है। पशुओं में पाए जाने वाले कीड़ प्रमख रूप से दो प्रकार के पाए जाते हैं। यदि ध्यान न दिया जाए तो ये काफी नुकसान पहुंचाते हैं।

पेट में कीड़ों के प्रकार: पशुओं के शरीर के अन्दर पाये जाने वाले परजीवी कृमि भौतिक संरचना के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। पहला चपटे व पत्ती के आकार के जिन्हें हम पर्ण कृमि एवं फीता कृमि कहते हैं। दूसरे गोल कृमि, जो आकार में लम्बे गोल बेलनाकार होते हैं। इसके अलावा कई प्रकार के कीड़ें पाए जाते हैं।

पर्ण कृमि यह परजीवी पत्ती के आकार की संरचना के होते है इसलिए इन्हें पर्ण कृमि कहते हैं। यह कृमि छोटे बच्चों में ज्यादा होते हैं। ये कीड़े पशुओं में होने के 15 दिन बाद लक्षण दिखते हैं। इसमें पशु चारा नहीं खाता है। उसकी आंखों से पानी गिरने लगता है, पशु सुस्त हो जाता है। खून की कमी होने से पशु कमजोर होता चला जाता है। गोबर भी नहीं करता है।

फीताकृमि इस परजीवी का शरीर चपटा होता है। इनका आकार कुछ मिलीमीटर से लेकर अनेक मीटर तक लम्बा हो सकता है इनक चपटे शरीर एवं लम्बे आकार के कारण इन्हें फीता कृमि भी कहा जाता है। यह परजीवी ज्यादातर पशुओं के भोजन नाल में पायें जाते हैं। गोलकृमि इन परजीवी का शरीर बेलनाकार होने के कारण इन्हें गोल कृमि कहते हैं। यह प्राय बड़े पशुओं में होता है। उनका पेट गोल होने लगता है। यह परजीवी पशुओं में खून चूसने के कारण अनीमिया, भोजन इस्तेमाल न करने के कारण कमजोरी, फेफड़ों में होने के कारण निमोनिया, आंखों में होने के कारण अन्धापन, आदि कई विभिन्न बीमारियों को बढ़ाता है।

लीवर फ्लूक यह बीमारी पशुओं में परजीवी (फैसियोला) से होती है। पशु जब नदी तालाबों एवं पोखरों के पास घास चरने जाते हैं, तो उसमे पाये जाने वाले घोघा में सेफैसियोला हीपेटिका नामक कीड़े निकलकर घास की पत्तियों में छिप जाते है। जब पशु इस घास को खाता है तो यह उनके पेट में से लीवर तक चले जाते है। इस रोग से संक्रमित होने के बाद पशुओं के लीवर पर प्रभाव पड़ता है और समय पर उपचार नहीं मिलने पर लीवर फट भी जाता है, जिससे पशु की मौत हो जाती है। इसमें बारिश के बाद पशु को तालाब और पोखरों के किनारे न चरने दें। भूख कम लगना, बदबूदार दस्त होना, दूध उत्पादन में कमी, गले के नीचे सूजन होना इसके लक्षण है।

कृमि कैसे पशु के शरीर मे पहुंचते है: संक्रमित पशु के गोबर में कृमि के अंडे उपस्थित होते है और जब यह संक्रमित पशु चरागाह में गोबर करता है तो गोबर के साथ- साथ कृमि के अंडे भी आते है। संक्रमित पशु का गोबर पशुओं के चलने के कारण आस-पास घास में बिखर जाता है और इसके साथ ही कृमि के अंडे घास में लग जाते है और जब स्वास्थ्य पशु यहाँ घास चरने आते है या यह घास पशु को खिलायी जाती है तो पशु घास के साथ साथ कृमि के अंडे भी पशु के शरीर में चले जाते हैं। दूषित और संक्रमित पानी पीने से भी कृमि का संक्रमण हो जाता है। कृमि के अंडे अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, जिनको हम नग्न आखों से नहीं देख सकते। कृमि के अंडे पशु के शरीर में कृमि में परिवर्तित हो जाते हैं।

लक्षण: पशुओं के पेट मे कृमि धीरे-धीरे पशु को संक्रमित करते हैं इसके कारण पशुओं में मुख्य लक्षण देखने को मिलते है जैसे-पशु सुस्त और कमजोर दिखता है, अचानक वजन कम होना,मैटमेले रंग के बदबूदार दस्त आते हैं, गोबर में खून व कीड़े दिखना, पशु के चारा खाते हुए भी शरीर की वृद्धि कम और पेट का बढ़ जाना, शरीर की हड्डियां दिखने लगना, पशु में खून की कमी होना, अचानक दूध कम कर देना, गर्भधारण में परेशानी।

पशुओं में कृमि का संक्रमण आम है और उनकी वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं। हालांकि ज्यादातर मामलों में, कृमि संक्रमण पशु जीवन के लिए खतरा नहीं है, लेकिन यह विभिन्न नैदानिक समस्याओं को जन्म देता है। इसलिए बछड़ो और बड़े पशुओं दोनों के लिए कृमिनाशक दवा महत्वपूर्ण है। उपचार आमतौर पर सरल होता है, लेकिन शुरुआती पहचान, विशेष रूप से बछड़ो में विकास की कमी और बछड़ो की मृत्यु दर को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है। यदि आपका पशु किसी ऐसे क्षेत्र में रहते हैं या किसी ऐसे क्षेत्र मे चरने जाते हैं जहां पशुओ को विशेष रूप से आंतों के कीड़े विकसित होने का खतरा होता है, तो पशुओं और बछड़ो दोनों के लिए साल में कम से कम चार बार डीवॉर्मिंग करना और स्वच्छता पर अतिरिक्त ध्यान देना अच्छा होता है। वयस्क पशुओं में डीवॉर्मिंग प्रत्येक तीन महीनों के अंतराल मे कर देना चाहिए। बछड़े की डीवॉर्मिंग की शुरुवात सात दिन की उम्र में, फिर एक महीने के अंतराल से छह महीने की आयु तक डीवॉर्मिंग करते है , इसके पश्चात तीन महीने के अंतराल से डीवॉर्मिंग करते है।

चिपको आंदोलन: जब महिलाओं ने पेड़ों को कटने से बचा कर रचा इतिहास

26 मार्च 1974 को आज के उत्तराखंड के चमोली जिले में एक आंदोलन हुआ, जिसमें पेड़ काटने के प्रयास हुए और वहां की स्थानीय महिलाओं ने किसी बड़े नेता के नेतृत्व की जगह खुद अपने ही दम पर सैकड़ों पेड़ों को कटने बचाया और चिपको आंदोलन ऐतिहासिक हो गया। महिलाओं ने इस अनोखे अहिंसक आंदोलन की मदद से जंगलों में पेड़ों की कटाई को रोका था। इसमें गढ़वाल हिमायल के लाता गांव में गौरा देवी के नेतृत्व में केवल 27 महिलाओं के समूह ने यह साहसिक कारनामा कर दिखाया था।

दरअसल चमोली में वन विभाग के ठेकेदार पेड़ों की कटाई कर रहे थे जिसका विरोध स्थानीय लोग कर रहे थे उनका दावा था कि इन पेड़ों पर उनका परंपरागत अधिकार है। आंदोलन की शुरुआत 1973 के शुरू में हुई जब उत्तराखंड क्षेत्र के चमोली जिले के भट्ट और दशोली ग्राम स्वराज्य मंडल के नेतृत्व में ग्रामीणों ने एक निजी कंपनी को 14 पेड़ों को काटने से रोका। 24 अप्रैल को हुई इस घटना के बाद दिसंबर एक बार फिर ऐसा हुआ जब गांव वालों ने गोपेश्वर से करीब 60 किमी दूर फाटा रामपुर के जंगलों में उसी कंपनी के एजेंटों को फिर पेड़ों की कटाई से रोका। 1974 में वन विभाग में जोशीमठ ब्लॉक के रैणी गांव केपास पेंग मुरेंडा जंगल को कटाई के लिए 680 हेक्टेयर से अधिक जंगल की नीलामी की थी। कटाई रोकने के लिए रैणी गांव की महिलाओं ने महिला मंडल की प्रधान गौरा देवी के नेतृत्व में पेड़ों पर चिपक कर अपना विरोध प्रदर्शन किया। महिलाओं ने पेड़ काटने आए लोगों को समझाने की कोशिश की लेकिन जब वे नहीं माने तो महिलाओं ने पेड़ों से चिपक कर उन्हें चुनौती दे डाली कि पेड़ काटने से पहले उन्हें काटना होगा। यह अहिंसावादी तरीका बहुत ही कारगर रहा और ठेकेदार और उनके कटाई करने वाले मजदूरों को निराश होकर खाली हाथ जाना पड़ा। इस अनोखे तरीके से पेड़ों को बचाने की तरीके ने इस आंदोलन को देश भर में रातोंरात प्रसिद्ध कर दिया और जब महिलाओं ने वन विभाग के अधिकारियों के सामने अपनी समस्या रखी तो उन्हें ध्यान से सुनना पड़ा और उन पर काम भी करना पड़ा। बहुत से लोग इसे ही चिपको आंदोलन की शुरुआत भी मानते हैं। उस समय चमोली जिला उप्र में था और बात सरकार तक पहुंची और तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा को इस पर विचार करने के लिए एक कमेटी का गठन करना पड़ा और उसका भी फैसला उत्तरांचल के लोगों के हक में आया। शायद देश के बाकी लोगों को हैरत हो, लेकिन हकीकत यह है कि चिपको आंदोलन भारत के उत्तर हिमालय के इलाकों के लिए एक मिसाल बन गया है, जो आज भी पर्यावरण के लिए यहां के लिए लिए जाने वाले फैसलों को प्रभावित करता है। आज भी यहां भूस्खलन, भूकंप, बाढ़ आदि से भारी नुकसान होते देखने को मिल रहे हैं, जो चिपको आंदोलन की याद दिलाते हुए पर्यावरण के प्रति और ज्यादा संवेदनशील होने को प्रेरित ही नहीं बल्कि मजबूर तक कर रहे हैं।

ग्रीन गोल्ड किसान | बड़वानी में बांस की खेती कर रहे मित्र से मिली मदद

» तीन साल में तय मापदंड के अनुसार 120 रुपए प्रति पौधे का अनुदान

» रविंद्र ने खेत में 13 बाय 13 फीट की दूरी पर बांस के पौधे लगाए

यूट्यूब पर देखी हरे बांस की खेती 30 बीघा में लगा दिए 5 हजार पौधे

गंजबासौदा। जागत गांव हमार

मध्यप्रदेश के विदिशा जिले में गंजबासौदा से करीब 40 किलोमीटर दूर त्योंदा तहसील। यहां के मैनवाड़ा गांव के रहने वाले 38 साल के किसान रविंद्र रघुवंशी ग्रीन गोल्ड की खेती को लेकर चर्चा में हैं। दरअसल, खेती किसानी की दुनिया में हरे बांस को ग्रीन गोल्ड कहा जाता है, क्योंकि इसकी खेती से सोने जैसा ही प्रॉफिट होता है। मौसम की बेरुखी से घबराए किसान अक्सर फसलों को लेकर चिंतित रहते हैं, लेकिन रविंद्र अपनी बांस की फसल को लेकर निश्चिंत हैं। क्योंकि उनके बांसों पर प्राकृतिक आपदा का प्रभाव नहीं पड़ता। वन विभाग द्वारा कृषि क्षेत्र में बांस की खेती को बढ़ावा देने की जानकारी मिलने के बाद उन्होंने यूट्यूब पर बांस की खेती के बारे में जानकारी जुटाई। वहीं, बड़वानी में बांस की खेती कर रहे उनके मित्र के जरिए उन्हें मदद मिली। उन्होंने इंदौर की कंपनी के जरिए 30 बीघा जमीन पर बांस के पौधे लगाए। वन विभाग द्वारा रोपित बांस के पौधों के लिए तीन साल में निर्धारित मापदंड के अनुसार 120 रुपए प्रति पौधे का अनुदान दिया जाता है। रविंद्र को वन विभाग से अभी तक चार लाख का अनुदान मिल चुका है।

दो साल पहले लगाए थे पौधे

रविंद्र रघुवंशी ने यूट्यूब पर हरे बांस की खेती देखकर 5,200 पौधे लगाए थे। पौधे 2 साल पहले जून-जुलाई माह में लगाए थे। दो साल बाद अब 10 से 15 फीट ऊंचाई तक पहुंच चुके हैं। आने वाले 2 से ढाई साल में बांस बेचने लायक हो जाएंगे। बांस की ऊंचाई जैसे-जैसे बढ़ती जा रही है, वैसे-वैसे रविंद्र रघुवंशी का आत्मविश्वास और उत्साह दोगुना होता जा रहा है। भविष्य में किसान ने बांस के 5 हजार और पौधे लगाने का फैसला लिया है। रविंद्र रघुवंशी गंजबासौदा तहसील के एकमात्र ग्रीन गोल्ड मैन बन गए हैं।

इंटरक्रॉपिंग के जरिए लेते हैं दूसरी फसलें

रविंद्र ने खेत में 13 बाय 13 फीट की दूरी पर बांस के पौधे लगाए हैं। जो जगह खाली रही, उसमें गेहूं, मसूर, सोयाबीन और चने की फसल ले रहे हैं। इस प्रक्रिया में वह ट्रैक्टर के जरिए आसानी से दोनों मौसम की फसलों की बोवनी कर देते हैं। बांस की फसल पर रोग या मौसम परिवर्तन का असर नहीं पड़ता। बांस की खेती पर्यावरण संतुलन में भी सहयोग करती है।

बांस से बनते हैं कई उत्पाद

बांस की खेती एक बार लगाकर 100 वर्षों तक कटिंग करते हुए बांस के उत्पाद निर्माण टोकरी बांस सूप, दोना, पानी की बोतल, कपड़े, कागज, अगरबत्ती, फर्नीचर एवं अन्य सजावटी सामान का निर्माण करते हुए अपना रोजगार कर सकते हैं। बांस की खेती से पर्यावरण संतुलित रखता है। पीपल के पेड़ के बाद बांस ही वातावरण में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन छोड़ता है। हमारे पूर्वज अपने घर आंगन में बांस लगाते थे। मान्यता है कि यह शुभ का प्रतीक है। नए जीवन, विवाह, अंत्येष्टि जैसे कार्यक्रम भी बांस के बिना कार्य अधूरा है। बांस के इन फायदों को देखते हुए इसे हरा सोना भी कहा जाता है।

राज्य सरकार भी दे रही सहायता

राष्ट्रीय बांस मिशन के तहत किसानों को बांस की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें आर्थिक अनुदान दिया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में ही रोजगार और आय सृजित करने के उद्देश्य से सरकार ने राष्ट्रीय बांस मिशन का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बांस की खेती और इसके प्रसंस्करण के लिए लघु और कुटीर उद्योगों को भी बढ़ावा देना है। इससे शहरों की तरफ पलायन रुकेगा। बांस उत्पादन के क्षेत्र में देश आत्मनिर्भर बनेगा। योजना के तहत किसानों को सरकारी नर्सरी से बांस के मुफ्त पौधे देने का प्रावधान है। राष्ट्रीय बांस मिशन के तहत किसानों को बांस की नर्सरी लगाने के लिए 120 रुपए प्रति पौधे की सहायता राशि भी दी जाएगी। सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता राशि में 50 प्रतिशत खर्च किसान, जबकि अन्य 50 प्रतिशत लागत खुद सरकार द्वारा वहन करेगी। सरकार द्वारा प्रस्तावित 50 प्रतिशत अनुदान में 60 प्रतिशत हिस्सा केंद्र सरकार और 40 प्रतिशत हिस्सा सरकार की तरफ से देय होगा। इससे किसान चिंतामुक्त होकर बांस की खेती कर सकेंगे।

खास मिट्टी की जरूरत नहीं

वन विभाग ने बांस की खेती को हरी घास की श्रेणी में रखा है, इसलिए इसे काटने या परिवहन में अनुमति की आवश्यकता नहीं रहती। रविंद्र का कहना है कि बांस की फसल के लिए खास मिट्टी की जरूरत नहीं होती। जहां घास, वहां बांस हो सकता है। किसान चाहे, तो खेत की मेड़ पर भी फसल लगा सकते हैं, जिससे खेत का तापमान 2 डिग्री से भी कम बना रहता है। जानवरों से भी खेत की सुरक्षा की जा सकती है।

एटीएम की तरह बांस की खेती

बांस की खेती के लिए भी सरकारों द्वारा विशेष अभियान चलाए जाने से किसानों का रुख इस तरफ बढ़ रहा है। रविंद्र ने बताया कि उन्होंने बांस की कटंगा प्रजाति से आने वाली बंबूसा बंबू को लगाया है। इसके एक बांस का वजन 30 से 35 किलो रहता है जो 100 से लेकर 200 रुपए तक बिकता है। यह प्रजाति मध्यप्रदेश की जलवायु के हिसाब से विकसित की गई है। किसान का कहना है कि बांस की खेती एटीएम की तरह है, जिसका आप जब चाहे उपयोग कर नकद पैसा ले सकते हैं।

बांस की खेती के लिए मिट्टी और जलवायु

बांस की खेती करने वाले इच्छुक किसान सर्वप्रथम मिट्टी की जांच करवाएं और अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क करें। बांस की उन किस्मों का चुनाव करें, जिनका बाजार आसानी से उपलब्ध हो, या जिनसे अधिक लाभ मिल सके। बांस की खेती के लिए बलुई या दोमट मिट्टी सबसे अनुकूल रहती है। मिट्टी का पीएच मान भी 6.5 से 7.5 तक ही होना चाहिए। आमतौर पर बांस की नर्सरी मार्च के महीने में तैयार की जाती है। भारत में बांस की कुल 136 किस्में पाई जाती हैं। इसमें सबसे ज्यादा लोकप्रिय प्रजातियां बम्बूसा ऑरनदिनेसी, बम्बूसा पॉलीमोरफा, किमोनो बेम्बूसा फलकेटा, डेंड्रो कैलेमस स्ट्रीक्स, डेंड्रो कैलेमस हैमिलटन, मेलोकाना बेक्किफेरा, ऑकलेन्ड्रा ट्रावनकोरिका, ऑक्सीटिनेनथेरा एबीसिनिका, फाइलोंस्तेकिस बेम्बूसांइडिस, थाइरसोस्टेकिस ऑलीवेरी आदि है। इनकी खेती अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा एवं पश्चिम बंगाल के अलावा उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह आदि राज्यों में की जा रही है, लेकिन अब दूसरे राज्यों में भी जागरूक किसान इसकी खेती करने लगे हैं।

मोटे अनाज की किस्मों को लेकर अब तक करीब पांच हजार लोगों को जागरूक कर चुकी हैं। अग्रणी महाविद्यालय की पर्यावरणविद्, शिक्षाविद् और ईको क्लब की सदस्य डॉ. सत्य के अनुसार सतपुड़ा के घने जंगल में पाई जाने वाले दुर्लभ औषधीय पौधों और मोटे अनाज का पर्यावरणीय, सामाजिक व धार्मिक कार्यों में विशेष महत्व है।

20 साल में पांच हजार लोगों को किया जागरूक

-50 से अधिक सहेजी विलुप्तप्राय औषधीय प्रजातियां

वीणा ने दुर्लभ औषधीय प्रजाति और मोटे अनाज को बचाने का उठाया बीड़ा

बड़वानी। जागत गांव हमार

बड़वानी जिले की पर्यावरणविद् 57 वर्षीय डॉ. वीणा सत्य ने पश्चिमी मध्यप्रदेश के सतपुड़ा के घने जंगलों में पाई जाने वाली विलुप्त हो रही औषधीय प्रजातियों को रिसर्च कर उन्हें सहेजने का बीड़ा उठाया है। इनको अपने घर के आंगन और शासकीय महाविद्यालय के बगीचे में लगाकर संरक्षण करने के साथ ही महत्ता बता रही हैं। वहीं पश्चिम निमाड़ में दूरस्थ ग्रामीण अंचल में मिलने वाले मोटे अनाज की किस्मों को भी सहेजा है। इन औषधियों व मोटे अनाज की किस्मों को लेकर अब तक करीब पांच हजार लोगों को जागरूक कर चुकी हैं। अग्रणी महाविद्यालय की पर्यावरणविद्, शिक्षाविद् और ईको क्लब की सदस्य डॉ. सत्य के अनुसार सतपुड़ा के घने जंगल में पाई जाने वाले दुर्लभ औषधीय पौधों और मोटे अनाज का पर्यावरणीय, सामाजिक व धार्मिक कार्यों में विशेष महत्व है। बड़वानी जिले के साथ ही पश्चिम मध्य प्रदेश के अन्य जिलों धार, खरगोन, आलीराजपुर, पचमढ़ी एवं महाराष्ट्र सीमा के तोरणमाल आदि क्षेत्रों की औषधीय संपदा और मछली मारक पौधों, स्पर्श चिकित्सा में उपयोगी, गर्भ निरोधक पौधों, आलीराजपुर जिले के देव वनों और इनमें संरक्षित पौधों तथा हर्बल पेस्टिसाइड पर भी शोध कार्य किया है। उनके 20 शोध पत्र विभिन्न राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय जर्नल्स में प्रकाशित हो चुके हैं। उनके द्वारा 18 राष्ट्रीय और 17 अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठियों में शोध पत्र प्रस्तुत किए गए हैं। 10 संगोष्ठियों में वे विषय विशेषज्ञ के रूप में पर्यावरण और जैव विविधता संरक्षण पर व्याख्यान दे चुकी हैं।

इन औषधीय पौधों को सहेजा

डॉ. सत्य ने जंगल में विलुप्त हो रही प्रजातियों जैसे केव कंद (त्वचा रोग के लिए उपयोगी), जंगली केला (पागलपन के इलाज के लिए), गूगल (कोलेस्ट्रोल और शुगर नियंत्रण), गजपिपली, सर्पगंधा (उच्च रक्तचाप के इलाज के लिए), ब्राह्मी बूटी (स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए), अन्तमूल (अस्थमा के लिए), काली हल्दी (श्वांस रोगों के लिए), शतावरी (दुग्ध वृद्धि के लिए), सफेद गुंज, गुडमार (मधुमेह के इलाज के लिए) आदि को शासकीय महाविद्यालय के औषधीय उद्यान और अपने घर के आंगन में लगाकर इनका संरक्षण करने के साथ ही पर्यावरणीय, सामाजिक व धार्मिक कार्यों में महत्व बता रही है। इसके साथ ही विलुप्तप्राय प्रजातियों जैसे पाडर, कुल्लु, श्योनक, तीनस, सीता अशोक, कनकचंपा, हर्रा, गधापलाश, कुम्भी, हल्दू, धावडा, मालकांगनी आदि को भी महाविद्यालय के वानस्पतिक उद्यान में संरक्षित किया है।

ग्रीन चैंपियन अवॉर्ड भी प्राप्त हो चुका

डॉ. सत्य जैव विविधता के संरक्षण के लिए वन विभाग के साथ, मध्य प्रदेश बायोडायवर्सिटी बोर्ड और छत्तीसगढ़ बायोडायवर्सिटी बोर्ड के साथ भी कार्य कर रही हैं। उनके संरक्षण के कार्यों के लिए महाविद्यालय को राज्य स्तरीय बायोडायवर्सिटी पुरस्कार और जिले का ग्रीन चैंपियन अवार्ड भी प्राप्त हो चुका है। पर्यावरण संरक्षण के लिए वे पर्यावरण नियोजन और प्रबंधन संस्थान, भोपाल के साथ महाविद्यालय के ईको क्लब समन्वयक के रूप में कार्य कर रही हैं। ऊर्जा संरक्षण, जल संरक्षण, तथा पर्यावरण संरक्षण पर विद्यार्थियो को जागरूक करने के लिए कार्यशालाएं, सेमिनार, पोस्टर, क्विज, निबंध, स्लोगन प्रतियोगिताएं आदि आयोजित की हैं।

पर्यावरणविद डॉ. वीणा सत्य द्वारा शासकीय अग्रणी महाविद्यालय में विलुप्तप्राय विशेष औषधीय पौधों का उद्यान तैयार कर नवाचार किया गया है। उनके प्रयासों के माध्यम से हजारों विद्यार्थी व ग्रामीण जागरूक हुए हैं। महाविद्यालय द्वारा आगे भी सतपुड़ा के जंगल में रिसर्च के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

-डॉ. एनएल गुप्ता, प्राचार्य शासकीय अग्रणी महाविद्यालय, बड़वानी

खुद का अनाज बैंक: ग्रामीण क्षेत्रों में ज्वार 60, मक्का 26, चावल 50 और मोटे अनाज (श्री अन्न) की 28 देशी किस्मों पर शोध कार्य कर इनके बीजों को संरक्षित किया है। खुद का अनाज बैंक भी बनाया है।

देश में 21 हजार पशुधन पर एक चिकित्सक, 10 हजार पद रिक्त

चार करोड़ पशुधन के लिए आठ हजार चिकित्सकों की दरकार

भोपाल। जागत गांव हमार

पिछले कुछ वर्षों से पशुओं से इंसानों में आने वाली बीमारियां बढ़ी हैं। इसके भी बाद भी स्थिति यह है कि देशभर में पशु चिकित्सकों के 10 हजार पद रिक्त हैं। भारत में 54 करोड़ पशुधन हैं। इस लिहाज से 21 हजार पशुओं पर एक चिकित्सक है, जबकि पांच हजार पर एक होना चाहिए। पशु चिकित्सकों की कमी की वजह से उनकी बीमारियां जल्दी से पकड़ में नहीं आ पातीं। पशुधन के संक्रमित होने पर रोकथाम में भी मुश्किल आती है। वेटरनरी काउंसिल आफ इंडिया (वीसीआइ) ने रिक्त पदों को भरने की पहल की है। इसके लिए सभी राज्यों से स्वीकृत अैर खाली पदों की जानकारी मांगी गई है। पशु चिकित्सकों की उपलब्धता के मामले में मध्य प्रदेश की स्थिति भी ठीक नहीं है। यहां करीब चार करोड़ पशुधन हैं। पांच हजार पशुधन पर एक चिकित्सक के मान से आठ हजार चिकित्सकों की आवश्यकता हैं, पर स्वीकृत पद सिर्फ 1671 हैं। इनमें भी 289 रिक्त हैं। इस वजह से पशुओं की नियमित जांच और टीकाकरण जैसे काम भी नहीं हो पा रहे हैं।

चार सौ मवेशी देख रहे पांच डॉक्टर

स्थिति यह है कि भोपाल स्थित राज्य पशु चिकित्सालय की ओपीडी में हर दिन करीब चार सौ मवेशी उपचार के लिए लाए जाते हैं, पर डॉक्टर सिर्फ पांच हैं। इनकी तीन पाली में ड्यूटी लगती है। संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं डॉ. आरके मेहिया ने बताया कि 129 डाक्टरों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है। यह डॉक्टर जल्द मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा डाक्टरों के 80 और पदों पर भी जल्द ही भर्ती शुरू की जाएगी।

इस समय मनुष्य तक पहुंचने वाली संक्रामक बीमारियों में ज्यादातर पशुओं से आ रही हैं। इसमें एंथ्रेक्स और बर्ड फ्लू भी शामिल है। इन्हें जूनोटिक बीमारियां कहा जाता है। इन्हें फैलने से रोकने के लिए पर्याप्त पशु चिकित्सक होना जरूरी है। हमारी कोशिश है कि राज्यों में रिक्त पदों को भरा जाए।

- डॉ. उमेश चंद्र शर्मा, अध्यक्ष, वेटरनरी काउंसिल आफ इंडिया

पंचायतों में एक मॉडल तैयार करने का लक्ष्य कृषि विभाग ने बनाया

गुड़-बेसन, गौमूत्र और गोबर से 100 गांव के किसान करेंगे प्राकृतिक खेती

भिंड। जागत गांव हमार

प्राकृतिक खेती के दायरे को बढ़ाने के लिए पंचायतों में एक मॉडल तैयार करने का लक्ष्य कृषि विभाग ने बनाया है। जीरो बजट की इस खेती को परंपरागत बनाने के लिए जिले के 100 गांव में पांच-पांच किसानों का चयन किया जाएगा। प्रत्येक किसान को प्रशिक्षण देकर एक-एक एकड़ में प्राकृतिक तरीके से फसलें उगाई जाएंगी। पिछले एक साल में 300 कृषकों ने प्राकृतिक पद्धति को अपनाकर मृदा को अपशिष्ट से मुक्त किया है।

एक गाय से होगी 30 एकड़ खेती- एक गाय से किसान 30 एकड़ भूमि में प्राकृतिक खेती कर सकते हैं। कृषि विभाग के उप संचालक आरएस शर्मा ने बताया देशी गाय के गोबर, गोमूत्र में अधिक पोषक तत्व होते हैं जो मृदा की उपजाऊ क्षमता को विकसित करते हैं। वर्ष 2024 तक जिले के 500 एकड़ में प्राकृतिक खेती करने का लक्ष्य तय किया है। इसके लिए आत्मा विभाग द्वारा किसानों को नियमित प्रशिक्षण देकर खेती के तरीके बताए जा रहे हैं। जो किसान पहले से इस खेती को कर रहे हैं, वे चार गुना तक बिना लागत के लाभ कमा रहे हैं।

कृषि विभाग द्वारा केंद्र सरकार की पहल पर यूरिया, डीएपी जैसे केमिकलयुक्त खाद की जगह जैविक व प्राकृतिक खेती को बढ़ाया दिया जा रहा है। किसानों को इस खेती के लिए कृषि वैज्ञानिकों और आत्मा के द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अधिकारी खेतों पर पहुंचकर निरीक्षण कर रहे हैं। किसान की खेती में लागत कम करके सवस्थ धरा और स्वस्थ मानव के उद्देश्य को पूरा करने की अवधारणा कृषि विभाग कर रहा है।

ऐसे करें प्राकृतिक खेती

देशी गाय के तरल खाद के प्रयोग से प्राकृतिक खेती की जाती है। खाद बनाने के लिए 6 से 8 लीटर गोमूत्र, 7 से 8 किलो गोबर, आधा किलो गुड़ और 250 ग्राम बेसन के साथ एक किलो मिट्टी का ड्रम में घोल तैयार करते हैं। तीन से चार दिन के लिए इस घोल को ढककर रख देते हैं, जिसके बाद छानकर तरल खाद के रूप में फसल को दिया जाता है। गोहद के सिरसोदा गांव के किसान रामगोपाल गुर्जर 20 एकड़ में प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। खेतों में उन्होंने इस वर्ष चार बेराइटी के आलू, जिसमें चिपसोना वन, पुखराज, कुफरी पुखराज लगाए हैं। इसके अलावा टमाटर, बैगन, चना, अरहर की फसल लहलहा रही है। गोहद में प्राकृतिक आलू 40 रुपए तक बेचा जा रहा है।

प्राकृतिक खेती के फायदे

- मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ती है।
- सिंचाई का अंतराल बढ़ जाता है।
- रासायनिक खाद पर निर्भरता कम होती है।
- फसल की लागत में कमी आती है।
- फसलों की उत्पादकता बढ़ जाती है।

जायद मूंग की उन्नत उत्पादन तकनीक

डॉ. सर्वेश कुमार, मुकेश बंकोलिया, डॉ. ओपी भारती, डॉ. एसके तिवारी, डॉ. संध्या मुरे
वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केन्द्र, हरदा

हरदा। पिछले 8-10 वर्षों में मूंग की अनेक प्रजातियां विकसित की गयी हैं। इनमें से अधिकांश प्रजातियां प्रमुख रोगों और कीटों के प्रति अवरोधी है। इसके अलावा ये शीर्घ्र पकने वाली, फलियां एक साथ पकने वाली तथा बड़े आकार के दाने वाली हैं। ये नवीनतम प्रजातियां अधिक उत्पादक देने वाली भी हैं। इनकी उत्पादन क्षमता कुशल फसल प्रबंधन के अंतर्गत 12-17 क्विंटल/हेक्टेयर हैं। ये प्रजातियां परंपरागत प्रजातियों की अपेक्षा 15-20 प्रतिशत तक अधिक उपज देती है।

भूमि का चुनाव- ग्रीष्मकालीन मूंग फसल के लिए मध्यम से भारी भूमि उपयुक्त है।

खेत की तैयारी- रबी फसल गेहूं कटाई उपरान्त गेहूँ की नरवाई न जलाएं। रोटावेटर अथवा लोहे की भारी चौखटा (नरवाई तोड़ घिसटा यंत्र) को खेत में दो-तीन बार आड़ा-तिरछा चलायें इससे नरवाई टूटकर छोटे टुकड़ों में मिट्टी में मिल जायेगी। बुआई से पहले खेत अच्छी तरह तैयार करें। खेत में उचित नमी होने पर ही बुआई करें। भुरभुरे, बारीक व चूर्णिल खेत को मूंग की खेती के लिए अच्छा माना जाता है। खेत की दो तीन बार हैरो से जुताई करें। प्रत्येक जुताई के बाद पाटा अवश्य लगायें। जिससे भूमि की नमी संरक्षित बनी रहे। असिंचित व वर्षा आधारित क्षेत्रों में खेतों की मेड़बंदी करके वर्षा के पानी को बहने से रोकें, जिससे वर्षा जल का अधिकांश भाग मृदा अच्छी तरह से सोख लें।

बोवनी का उपयुक्त समय- बसंतकालीन/ग्रीष्मकालीन मूंग की बोवनी सामान्यत: मार्च के प्रथम सप्ताह से 15 अप्रैल के मध्य करें। गेहूं, आलू, गन्ना, चना और सरसों की कटाई उपरांत 70 से 80 दिनों में पकने वाली प्रजातियों की बुआई की जा सकती है। जिन क्षेत्रों में गेहूं की फसल देर से पकती है या किसी कारणवश खेत समय पर तैयार न हो तो वहां पर मूंग की 60 से 65 दिनों में पकने वाली किस्मों की बुआई 15 अप्रैल के बाद कर सकते हैं। ग्रीष्मकालीन मूंग की खेती उन्ही क्षेत्रों में करें जहां पर सिंचाई का पर्याप्त प्रबंध हो। मध्य नर्मदा घाटी में ग्रीष्मकालीन मूंग की बोवनी के लिए 25 फरवरी से 25 मार्च तक सबसे उपयुक्त समय है।

उन्नतशील किस्में-पूसा बैशाखी, पूसा विशाल, आई.पी.एम. 205-7 (विराट), एमएच 421, आईपीएम 410-3 (शिखा), पीडीएम 139, (सम्राट)

बीज की मात्रा- बसंतकालीन/ग्रीष्मकालीन मूंग की बुआई के लिए 25-30 किग्रा बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है। ग्रीष्मकालीन मूंग की पंक्तियों से पंक्तियों की दूरी 30 सेमी रखें। पंक्तियों में पौधे से पौधे की दूरी 8 से 10 सेमी रखें। बुआई हमेशा पंक्तियों में करें, जिससे फसल की निराई-गुड़ाई आसानी से की जा सके।

बीजोपचार- बीज बोने से पहले फफूंदीनाशक दवा से उपचारित अवश्य करें। इसके लिए फफूंदीनाशक दवा बाविस्टीन 2.5 ग्राम दवा

प्रति किग्रा बीज की दर से प्रयोग करें। इसके बाद बीज को थायोमेथोक्सम 70 डब्ल्यूएस 3 ग्राम प्रति किलो बीज से उपचारित करें जिससे सफेद मक्खी के प्रकोप को रोका जा सके तथा इसके बाद राइजोबियम जीवाणु से उपचारित करना अति आवश्यक है। इससे फसल द्वारा वायुमण्डलीय नाइट्रोजन के यौगिकीकरण क्रिया पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। बीज उपचार बुआई के 10-12 घंटे पहले कर लें। एक हेक्टर क्षेत्र में बुआई करने के लिए राइजोबियम जीवाणु के दो पैकेट पर्याप्त होते हैं। राइजोबियम उपचार के लिए एक लीटर पानी में 100 ग्राम गुड़ तथा दो ग्राम गोंद को अच्छी तरह उबाल लें। उसके बाद ठंडा होने पर इस घोल में राइजोबियम के दोनों पैकेट मिला दें। इस प्रकार बनी लेई को बीज के साथ अच्छी तरह से मिला दें, जिससे बीज के चारों और लेई की महीन परत चढ़ जाए। इसके बाद बीज को छाया में सुखा लें।

खरपतवार नियंत्रण

ग्रीष्मकालीन मूंग में खरपतवारों की कोई विशेष समस्या नहीं रहती है। सामान्यत- फसल की वृद्धि के साथ ही कई प्रकार के चौड़ी व संकरी पत्तियों वाले खरपतवार उग आते हैं, जो फसल को दिए गए पोषक तत्वों व पानी का अवशोषण कर लेते हैं, जिससे मूंग की पैदावार और गुणवत्ता में कमी आ जाती है। इस प्रकार किसान को अपनी फसल का अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाता है। बुआई के प्रथम 20-25 दिनों में खरपतवार फसल से ज्यादा स्पर्धा करते हैं। अत- बुआई के 15-20 दिनों के अंदर कसोले के निराई-गुड़ाई कर खरपतवारों को नष्ट कर दें। आजकल निराई गुड़ाई के लिए मजदूरों की कम उपलब्धता और उनकी अधिक मजदूरी के कारण खरपतवारों को नियंत्रण करने के लिए बहुत से शाकनाशी बाजार में उपलब्ध हैं। मूँग की बोनी उपरांत एवं अंकुरण पूर्व पेंडीमिथालीन (स्टाम्प एक्सट्रा) एक एकड़ में 600 मिली दवा को 200 लीटर पानी में घोलकर छिड़कें। फसल की 20-25 दिन की अवस्था पर डोरा या कुल्पा चलाएं।

सहफसली खेती

मूंग अल्प अवधि वाली फसल है। इसकी बढ़वार बहुत तेजी से होती है। ऐसी स्थिति में मूंग को अन्य फसलों के साथ सह फसल के रूप में उगाना लाभदायक है। ऐसा करने से किसानों को मुख्य फसल के साथ अतिरिक्त आय भी मिल जाती है। साथ ही सहफसली खेती से मुख्य फसल की पैदावार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। बसंतकालीन गन्ने क दो पंक्तियों के बीच में मूंग की दो पंक्तियां बोना लाभदायक पाया गया है। सहफसली खेती में खरपतवारों को भी पनपने का कम मौका मिलता है। इससे न केवल फार्म संसाधनों का उचित उपयोग होता है बल्कि प्रति इकाई क्षेत्र शुद्ध लाभ भी बढ़ता है।

सिंचाई प्रबंधन

मूंग की फसल में पानी की कम आवश्यकता होती है। ग्रीष्मकालीन/ बसंतकालीन मूंग की अच्छी वृद्धि व विकास के लिए 3-4 सिंचाई आवश्यक है।

खाद एवं उर्वरक प्रबंधन

खेत की मिट्टी की जांच के बाद ही खाद एवं उर्वरकों की मात्रा सुनिश्चित की जाये। मूंग के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस व पोटाश की सम्पूर्ण मात्रा बुआई के समय प्रयोग करें। राइजोबियम जैविक उर्वरक के प्रयोग द्वारा मूंग की पैदावार में 15-20 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जा सकती है। जीवाणु उर्वरक सस्ते और आसानी से उपलब्ध हैं तथा इनका प्रयोग भी सुगम है। फास्फोरस जड़ों के विकास के लिए पोषक तत्व है। बारानी व कम पानी वाले क्षेत्रों में फास्फोरस का प्रयोग करने से पौधों की जड़ें गहराई तक जाती हैं, जिससे पौधे गहराई से पानी और पोषक तत्वों का अवशोषण कर सकते हैं। मूंग की खेती में उत्पादन लागत कम करने के लिए फास्फेट घुलनशील जीवाणु का भी प्रयोग करें, जिससे मृदा में उपस्थित अघुलनशील फास्फोरस की उपलब्धता को बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए पीएसबी का 500 ग्राम का चार पैकेट प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है। मूंग में 20 किग्रा नत्रजन, 40 कि.ग्रा. पोटाश 20 कि.ग्रा. सल्फर एवं 25 किग्रा जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर का प्रयोग पर्याप्त होता है।

बीज उत्पादन में हो रहा अनुसंधान एवं विकास

भोपाल/नई दिल्ली। जागत गांव हमार

केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि नई किस्मों को विकसित करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) अपने 57 संस्थानों और 40 अखिल भारतीय संस्थानों के माध्यम से 45 राज्य/केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालयों में 930 से अधिक केंद्रों में संचालित समन्वित अनुसंधान परियोजनाएं/अखिल भारतीय नेटवर्क परियोजनाएं मुख्य रूप से अनाज और सब्जियों सहित विभिन्न फसलों के बीज/ किस्मों के सुधार पर शोध को बढ़ावा देती हैं। इसके अलावा, आठ विशेष परियोजनाएं जैसे नेशनल इनोवेशन ऑन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर (एनआईसीआरए), चार कंसोर्टियम रिसर्च प्रोजेक्ट्स इनसेंटिवाइजिंग रिसर्च इन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट नेटवर्क प्रोजेक्ट ऑन ट्रांसलेशनल जीनोमिक्स इन क्रॉप प्लांट्स और नेशनल एग्रीकल्चरल साइंस फंड भी बीज किस्मों में जलवायु परिवर्तन अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित करते हैं। मजबूत अनुसंधान प्रणाली के परिणामस्वरूप, 2022-23 में 323.055 मिलियन मीट्रिक टन और 2021-22 के दौरान 345.32 मिलियन मीट्रिक टन बागवानी फसलों का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। बीजों के निर्यात को बढ़ाने के लिए, भारत 2008 से आर्थिक सहयोग और विकास संगठन बीज योजना का सदस्य बन गया था। यह योजना ओईसीडी के दिशानिर्देशों के अनुसार अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए उत्पादित और संसाधित बीजों के लिए लेबल और प्रमाण पत्र के उपयोग और ओईसीडी सदस्य देशों को परेशानी मुक्त निर्यात के लिए अधिकृत करती है। यह योजना बाधाओं को दूर करके बीजों के निर्यात की सुविधा भी प्रदान करती है।

तोते खाने लगे अफीम, टेंशन में किसान, हो रहा नुकसान

मंदसौर। मध्य प्रदेश के मंदसौर, नीमच और रतलाम में अच्छी खासी संख्या में किसान अफीम की खेती करते नजर आते हैं। इसकी खेती के लिए किसानों को बकायदा केंद्रीय नारकोटिक्स विभाग से लाइसेंस लेना होता है। किसान नारकोटिक्स विभाग की देखरेख में ही इस फसल को उगा सकते हैं। अब यहां के किसानों की अफीम की फसल पर खतरा मंडराने लगा है। दरअसल तोते अफीम खाने लगे हैं। जिसकी वजह से किसानों को फसल के नुकसान का डर सता रहा है। तोतों के आतंक की वजह से किसानों की चिंताएं बढ़ गई है। अफीम की खेती करने वाले किसानों को अपनी उपज सरकार को देनी होती है। अगर किसान ऐसा नहीं कर पाते हैं तो सरकार द्वारा अफीम की खेती का उनका कांट्रेक्ट खत्म कर दिया जाता है। ऐसी स्थिति में कुछ किसानों ने तोतों से अफीम को बचाने के लिए अब प्लास्टिक की नेट लगानी शुरू की है।

किसान अपना रहे ये तरीका

प्लास्टिक की नेट लगाने से अफीम की फसल को पहले के मुकाबले कम नुकसान होने लगा है। पहले तोते भारी मात्रा में अफीम के डोडे अपनी चोंच में लेकर उड़ जाते थे। अब प्लास्टिक नेट लगने से ऐसे तोतों की संख्या कम हुई है। इन सबके अलावा नीलगायों का खतरा भी अफीम की खेती पर मंडरा रहा है।

सर्दी के मौसम में बढ़ जाती है डिमांड, गुड़ से मुनाफ के कारण गन्ने का रकवा भी हुआ दोगुना

अब गोराघाट के गुड़ की ब्राडिंग की भी की जा रही तैयारी

देश के कई राज्यों में पहुंच रही दतिया के 'गोरा गुड़' की मिठास

दतिया। जागत गांव हमार

दतिया के 'गोरा गुड़' की मिठास देश के कई राज्यों में पहुंचने लगी है। झांसी-ग्वालियर हाइवे किनारे बन रहा गुड़ अब दतिया की पहचान बन गया है। गोराघाट व सोनागिर क्षेत्र में गुड़ का उत्पादन बढ़ने से गन्ने की पैदावार भी बढ़ गई है। जिसके चलते यहां के किसान क्रेशर लगाकर गुड़ निर्माण करते हैं। सबसे मजेदार बात यह है कि स्थानीय किसानों के अलावा इन क्रेशर का संचालन करने मेरठ आदि क्षेत्र से लोग हर साल दतिया आते हैं। जो पूरे सीजन क्रेशर चलाकर गुड़ बनाकर मोटा मुनाफा कमाते हैं। दतिया का गुड़ एक जिला एक उत्पाद के लिए भी चुना गया है। वहीं अब गोराघाट के गुड़ की ब्राडिंग की भी तैयारी शुरू हो गई। इसके लिए इसे 'गोरा गुड़' का नाम दिया गया है। जल्दी ही यहां का गुड़ देश भर में अपनी अलग पहचान बनाएगा। इसे लेकर प्रशासन भी प्रयास में जुटा है। गोराघाट क्षेत्र में सर्दी के इन चार माह में करीब चार लाख क्विंटल गुड़ तैयार होता है।

हाइवे किनारे सजने वाली दुकानों पर यह गुड़ काफी मात्रा में बिकता है। वहीं मंडियों के माध्यम से भी दिल्ली, उप्र, राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र सहित देश के अन्य प्रदेशों तक 'गोरा गुड़' पहुंचने लगा है। पांच साल में जिले में गन्ने का रकबा लगभग दोगुना हो गया है। यहां गुड़ बनाने के छोटे होल्कू व भट्टियां न केवल सैकड़ों लोगों को रोजगार दे रहे हैं बल्कि किसानों का मुनाफा भी बढ़ाने में मददगार साबित हो रहे हैं।

एक सैकड़ा भट्टियां

गोराघाट क्षेत्र में करीब एक सैकड़ा से अधिक भट्टियों पर गुड़ तैयार होता है। यह काम उचाड़, सहित बड़ौनी और हिडौरा तक किया जाता है। यहां गुड़ उत्पादन के लिए मेरठ, हरियाणा, मुजफ्फरनगर आदि जगहों से भी लोग आते हैं। गोराघाट पर गुड़ उत्पादन के काम में लगे संचालित कर रहे मेरठ निवासी शेखर का कहना है एक क्रेशर पर पूरे सीजन में डेढ़ हजार क्विंटल गुड़ तैयार कर लेते हैं। यहां एक दिन में 12 क्विंटल गुड़ बनाया जाता है। सर्दी के मौसम में उत्पादन और बढ़ जाता है। गुड़ बनाने का काम माह नवंबर से लेकर अप्रैल तक यहां चलता है। इसी दौरान बाहर से लोग इस काम के लिए दतिया आते हैं।

रोजी रोटी का बना साधन

गुड़ उत्पादन का कारोबार 5 हजार से अधिक लोगों की रोजी रोटी का जरिया भी बना गया है। पूरे सीजन लोगों को गुड़ बनाने वाली भट्टियां रोजगार उपलब्ध कराती हैं। गुड़ उत्पादक रामसिंह के अनुसार गुड़ बनाने के छोटे कोल्हू व भट्टी पर भी कम से कम 25 लोगों को रोजगार मिलता है। बड़ी भट्टी पर यह संख्या 45 तक पहुंच जाती है। जिले में लगभग 170 गुड़ बनाने की भट्टियां संचालित हैं। इस हिसाब से 5 हजार से अधिक लोगों को गुड़ उत्पादन से रोजगार मिल रहा है। वहीं गोराघाट से सोनागिर तक हाइवे किनारे 70 से 80 दुकानें भी संचालित होती है। जो स्थानीय लोगों के लिए रोजगार का साधन है।

गन्ने का रकबा भी बढ़ने लगा

ग्राम उचाड़ में गन्ने की फसल बेचने गुड़ क्रेशर तक आने वाले किसानों ने बताया कि एक बीघा में करीब 100 से 130 क्विंटल तक गन्ने की पैदावार आसानी से हो जाती है। गन्ने की कीमत में भी इजाफा हुआ है। ऐसे में किसान को एक बीघा में सारा खर्चा काटने के बाद 30 हजार रुपये प्रति बीघा की कमाई हो जाती है। गन्ने का रकवा लगभग दोगुना होने का अंदाजा इसी आंकड़े से लगाया जा सकता है कि जब वर्ष 2018 में इस क्षेत्र में गन्ने का रकबा 5700 था जो वर्ष 2022-23 में 9460 हेक्टेयर हो गया।

एक जिला एक उत्पाद के लिए भी चुना गया गुड़

एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत दतिया जिले का प्रमुख उत्पाद गुड़ को चुना गया है। जिसके बाद गुड़ के प्रचार प्रसार को लेकर पूरा प्रशासन जुटा हुआ है। देश के हर राज्य तक दतिया के गुड़ की मिठास पहुंचे इसे लेकर बेहतर पैकिंग व मार्केटिंग शुरू की जा रही है। जिले के उद्योगपतियों व गन्ना उत्पादक कृषकों से भी इसे लेकर कलेक्टर संजय कुमार ने भी चर्चा की थी। एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत जिले में उन्नत किस्म के गन्ने की बंपर पैदावर को देखते हुए जिले को गुड़ हब के रूप में विकसित कर गुढ़ निर्माण के क्षेत्र में जिले की पहचान बने इसे लेकर गोराघाट सहित अन्य क्षेत्रों का प्रशासनिक अधिकारियों की टीम ने भ्रमण भी किया था। प्रयास किए जा रहे हैं कि जिले के गन्ना किसानों व गुड़ उत्पादकों को गुड़ के बाहर निर्यात से बेहतर दाम मिले सकें।

इस संबंध में काम शुरू किया गया है। एक जिला एक उत्पाद को लेकर बनाई गई नीति पर जिला प्रशासन कार्य करने में जुटा है। हमारे प्रयासों को सफलता मिलेगी। दतिया जिला जल्दी ही गुड़ हब के रूप में विकसित होगा।

- संजय कुमार कलेक्टर, दतिया

देश में भारतीय सेना को अब परोसा जाएगा मोटे अनाज से बना भोजन

भोपाल/नई दिल्ली। जागत गांव हमार

भारतीय सेना मोटे अनाज की खपत को बढ़ावा दे रही है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सैनिकों को दिये जाने वाले आहार में मोटे अनाज से तैयार किये गए आटे को शामिल किये जाने की शुरुआत की गई है। इस ऐतिहासिक निर्णय से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सैनिकों को करीब आधी शताब्दी के बाद देशी और पारंपरिक अनाज वाला राशन उपलब्ध कराया जाए, क्योंकि पहले के समय में गेहूं के आटे को बढ़ावा देने के लिए इन्हें बंद कर दिया गया था।

सभी रैंकों के लिए दैनिक भोजन का एक अभिन्न हिस्सा होगा- जैसा की भोजन में पारंपरिक मोटा अनाज इस्तेमाल करने से अनेक प्रकार के स्वास्थ्य लाभ होते हैं। इसके अलावा मोटे अनाज से तैयार किए गए खाद्य पदार्थ, हमारी भौगोलिक एवं जलवायु परिस्थितियों के अनुकूल जीवन शैली से संबंधित बीमारियों को दूर करने तथा सैनिकों की संतुष्टि और मनोबल बढ़ाने में महत्वपूर्ण कदम साबित होंगे। मोटा अनाज अब सेना में सभी रैंकों के लिए दैनिक भोजन का एक अभिन्न हिस्सा होगा।

बाजरा, ज्वार और रागी को वरीयता

सैनिकों को वर्ष 2023-24 से उपलब्ध कराए जाने वाले खाद्यान्न में अनाज (चावल और गेहूं का आटा) की अधिकृत पात्रता के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होने वाले मोटे अनाज से तैयार आटे की खरीद के लिए सरकार से अनुमति मांगी गई है। मोटे अनाज की सरकारी खरीद और इसका वितरण, इस्तेमाल किए गए अनाज के विकल्प तथा उसकी मांग पर तय मात्रा पर आधारित होगा। मोटे अनाज से तैयार आटे की तीन लोकप्रिय किस्में यानी बाजरा, ज्वार और रागी वरीयता को ध्यान में रखते हुए सैनिकों को उपलब्ध कराए जाएंगे। मोटा अनाज प्रोटीन, सूक्ष्म पोषक तत्वों और फाइटो-रसायनों का एक अच्छा स्रोत होता है। इसका काफी लाभ होता है, जिससे सैनिकों के आहार में पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता मिलती है। इसके अतिरिक्त, बड़े पैमाने पर आयोजित होने वाले कायक्रमों, बड़ाखानों, कैंटीनों और घर पर खाना पकाने के दौरान मोटा अनाज का व्यापक रूप से उपयोग करने के लिए परामर्श जारी किये गए हैं। मोटे अनाज से आरोग्यजनक, स्वादिष्ट और पौष्टिक व्यंजन तैयार करने के लिए रसोइयों को केंद्रीकृत प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। देश की उत्तरी सीमाओं पर तैनात सैनिकों के लिए गुणवत्तापूर्ण मोटा अनाज उत्पादों और हल्के-फुल्के नाश्ते को दिये जाने पर विशेष बल दिया गया है। सीएसडी कैंटीन के माध्यम से मोटे अनाज द्वारा निर्मित खाद्य पदार्थ पेश किए जा रहे हैं। साथ ही शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में इनकी बिक्री के लिए डेडिकेटेड कॉर्नर्स की स्थापना की जा रही है। शिक्षण संस्थानों में अपने मोटे अनाज को जानो जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है।

यूएमएमबी चॉकलेट खिलाने से बढ़ती है दूध देने की क्षमता

भोपाल। किसानों को लगता है कि हरी घास और अनाज खिलाने से ही गाय-भैंस अधिक दूध करती हैं। लेकिन एक नए शोध में इस बात का खुलासा हुआ है कि चॉकलेट खाने से भी मवेशियों की दूध देने का क्षमता बढ़ जाती है। ऐसे में अगर मवेशियों को चॉकलेट खिलाते हैं तो वह पहले के मुकाबले ज्यादा दूध देंगी। फिर आप दूध बेचकर अधिक कमाई कर सकते हैं। कुछ साल पहले बरेली स्थित भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने यूएमएमबी नाम से एक चॉकलेट बनाई थी। इस चॉकलेट की खासियत है कि इसे मवेशियों को खिलाने पर उसके अंदर दूध देने की क्षमता पहले के मुकाबले बढ़ जाती है। यानी आप अपनी गाय- भैंस से अधिक मात्रा में दूध निकाल सकते हैं। वैज्ञानिकों की मानें तो इस चॉकलेट के अंदर काफी अधिक मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं। इससे मवेशियों को अधिक एनर्जी मिलती है। इस चॉकलेट को केवल जुगाली करने वाले पशु ही खा सकते हैं। कई बार मवेशी बीमार पड़ जाते हैं। वे खाना-पीना भी छोड़ देते हैं। साथ ही जुगाली करना भी बंद कर देते हैं। शरीर कमजोर होने लगता है और दूध देने की क्षमता कम होने लगती है।

जागत गांव हमार के सुधि पाठकों...

» जागत गांव हमार कृषि, पंचायत और ग्रामीण विकास आधारित समाचार पत्र है, जिसके लिए आपका स्नेह और प्यार हमें शुरू से मिलता रहा है। हम आशा और विश्वास करते हैं कि आगे भी मिलता रहेगा।

» समाचार पत्र के लिए विशेषज्ञों की राय, प्रकाशन योग्य सामग्री के साथ-साथ आपके समक्ष इसे पहुंचाने तक हमारी जिम्मेदारी बड़ी चुनौतीपूर्ण है। आपके सहयोग से ही हम इस चुनौती का सामना कर पाएंगे।

» ऐसे में हमारी आपसे अपेक्षा और आग्रह है कि जागत गांव हमार के वार्षिक सदस्य बनें और इसके लिए नीचे लिखे गए नंबर पर संपर्क करें।

संपर्क करें- अजय द्विवेदी-9229497393, 94250485889

"आपका सहयोग हमारी मजबूती का आधार बनेगा"

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक अजय कुमार द्विवेदी द्वारा जय माता प्रिंटर्स, मं.नं.1, पेमदीपुरा बापू कालोनी के पास चिकलोद रोड, जहांगीराबाद, भोपाल(मप्र) से मुद्रित एवं एमआईजी 30, शिवकल्प, अयोध्या बाईपास भोपाल, मप्र से प्रकाशित। संपादक: अजय कुमार द्विवेदी, स्थानीय संपादक- **अरविंद मिश्र, संपर्क** -9229497393, 9425048589, ईमेल:- jagatgaon.bpl@gmail.com (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल होगा)